



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 157-2024/Ext.]

CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 14, 2024

(ASVINA 22, 1946 SAKA)

LEGISLATIVE SUPPLEMENT

CONTENTS

PART-I	ACTS	PAGES
	NIL	
PART-II	ORDINANCES	
	THE HARYANA SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) AMENDMENT ORDINANCE, 2024 (HARYANA ORDINANCE NO. 7 OF 2024).	43
PART-III	DELEGATED LEGISLATION	
	NIL	
PART-IV	CORRECTION SLIPS, REPUBLICATIONS AND REPLACEMENTS	
	NIL	

Authenticated.

Nayab Singh
Chief Minister, Haryana

PART-II
HARYANA GOVERNMENT
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 14th October, 2024

No. Leg. 20/2024.— The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 16th August, 2024, is hereby published for general information:-

HARYANA ORDINANCE NO. 7 OF 2024

**THE HARYANA SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) AMENDMENT
ORDINANCE, 2024**

AN

ORDINANCE

further to amend the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Ordinance, 2024.
2. In sub-section (1) of section 46 of the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014,-
 - (I) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) is or at the time of his retirement or resignation was a Judge of the High Court or a District Judge not having less than ten years standing on his superannuation;”;
 - (II) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) the Chairman shall be a Judge of High Court, if so appointed, and if a Judge of the High Court is not appointed, then the District Judge if so appointed and if the District Judge is also not appointed, then one of the three selected members of the Commission shall be the Chairman in the order of their seniority either in service or at Bar, as the case may be, and the term of the Chairman or the Member shall be five years from the date he assumes charge.”.

Short title.

Amendment of section 46 of Haryana Act 22 of 2014.

CHANDIGARH:
THE 16TH AUGUST, 2024.

BANDARU DATTATRAYA
GOVERNOR OF HARYANA

.....
RITU GARG,
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.

भाग-II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

संख्या लैज. 20/2024.— दि हरियाणा सिख गुरुद्वारा (मैनेजमेंट) अमेन्डमेन्ट ऑर्डिनन्स, 2024 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2024

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014

को आगे संशोधित करने के लिए

अध्यादेश

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. यह अध्यादेश हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 की धारा 46 की उप-धारा (1) में,—
(I) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(i) अपनी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के समय पर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश है या था, जिला न्यायाधीश के रूप में अपनी अधिवर्षिता पर कम से कम दस वर्ष की सेवा रखता हो;”
(II) खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(iv) अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया है, और यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता है, तो जिला न्यायाधीश होगा यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया है, और यदि जिला न्यायाधीश भी नियुक्त नहीं किया जाता है, तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक या तो सेवा में या बार में, जैसी भी स्थिति हो, उनकी वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्ष होगा, तथा अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष होगी:”।
2014 के
हरियाणा
अधिनियम 22
की धारा 46
का संशोधन।

चण्डीगढ़:
दिनांक: 23 अक्टूबर, 2024

बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

From

Additional Chief Secretary to Government of Haryana
Home Department.

To

The Secretary,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh

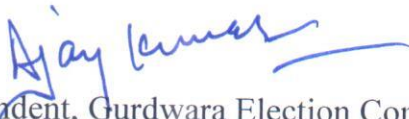
Memo No: 1/6/2014-3GE

Dated Chandigarh, the 07.11.2024

Subject:- THE HARYANA SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) ORDINANCE 2024.

.....
Reference on the subject noted above.

The copies of Ordinance No. 7 of 2024 dated 14.10.2024 issued vide Law and Legislative Department Notification No. Leg. 20/2024 dated 16.08.2024 respectively along with two copies duly authenticated by the Hon'ble Chief Minister is send herewith for further necessary action.


Superintendent, Gurdwara Election Commission,
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Home Department 